सोच रहे है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गुजरात में घरेलू गैस सिलडर्स का व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या सरकार इसकी जांच कराएगी ?

CAPT. SATISH SHARMA: Sir, I have already answered this question. I would like to repeat that it is our strategy to move outside the bigger towns, bigger cities and towns, into smaller towns so that the population in the country residing in the smaller towns also benefits from the sale of LPG. This is already underway. I have already answered this.

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : मैं ट्राइबल इलाके की बात कर रहा हूं । **(व्यवधान)**

CAPT. SATISH SHARMA: The present norms are: a population, consuming population, of 20,000 and above is considered for an outlet. As you know, the demand is more than the supply.

श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला : हमारे ट्राइबल इलाके मे मिटटी का तेल नहीं मिल रहा है **(व्यवधान)** गैस भी नहीं मिल रही है, उसके लिए सरकार क्या सोच रही है ? **(व्यवधान)**

CAPT. SATISH SHARMA: Sir, this question does not relate to kerosene. But I had mentioned earlier today, when we were discussing LPG, the kerosene factor. I totally agree ...*(Interruptions)*

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : आदिवासी तो जगह-जगह रहते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल : मिटटी का तेल भी नहीं मिल रहा है **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Is the Minister making some special arrangement for the tribals?

CAPT. SATISH SHARMA: Sir, let me clarify the basic issue here. The Central Government is supplying kerosene to all the States in the country at a subsidised rate. We are spending this year Rs. 4,000 crores on subsidy for the poor, the poorest of the poor. I am talking about kerosene. The idea is that the poorest of the poor all over the country, whether they are tribals or non-tribals, get the supply. Now, if kerosene is not reaching some parts of the country, if some tribals are not receiving it, it is the State Governments which are responsible there because the State Governments have to distribute it. The Centre only gives the quota to the States, to each State in the country.

*404| [*The Questioner (Shri Gopalsinh G. Solanki) was absent. For answer vide col....infra.*]

Construction of strategic road links to Myanmar by China

*405. DR. BAPU KALDATE:†
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that China is engaged in building strategic road links from the border towns to rail heads and sea ports of Myanmar;

(b) whether China is also helping the development of these ports; and

(c) if so, the details thereof and what is the reaction of Government of India in regard thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) to (c) Government are aware of reports that China is assisting Myanmar in construction

†The Question was actually asked on the floor of the House by Dr. Bapu Kaldate.

of roads, railways, ports and other infrastructure facilities in that country. Government keep all such developments under close watch and take appropriate steps as necessary to deal with them.

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है वह सभी देशों के साथ शांतिमय संबंधों की प्रस्थापना की है। मैं इस प्रश्न के माध्यम से कोई अशांतिपूर्ण बातों के बारे में आपका ध्यान नहीं खींचना चाहता। आपके ही नेतृत्व में कुछ महीने पहले आपके साथ हम चाइना भी गए थे। यह बात सही है कि आम तौर पर वहां भी एशिया का माहौल शांतिप्रिय ही है। ऐसा हमें नजर आया। लेकिन इस बात को हमको नहीं भूलना चाहिए कि चाइना ने जो दुर्व्यवहार हमारे साथ किया उसको नहीं भुलाना चाहिए। शांति चाहिए सौहर्द चाहिए, एक दूसरे की मदद होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अनुभव बहुत बुरा है। इस अनुभव के कारण इस प्रश्न को मैं उठाना चाहता हूं जैसे बर्मा में वे आजकल सड़कें, बंदरगाह या रेलवे स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं "थ्रेट परसेप्शन" की दिशा में सरकार डिफेंस की दृष्टि से किस नजरिए से, किस ढंग से देखती है यह मेरा पहला पूरक प्रश्न है।

श्री सलमान खुर्शीद : मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने बात उठाई है उस संदर्भ में हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हमने इस मामले की चर्चा चीन और म्यानामार दोनों के साथ शांतिप्रिय तरीके से की है और दोनों ही देशों ने हम को पूरी तरह से इस बात का विश्वास दिलाया है कि जो काम हो रहा है वह उनकी अपनी रक्षा से बढ़कर और किसी सिलसिले में नहीं जुड़ता है और किसी भी तरह से भारत की रक्षा पर कोई भी किसी किस्म का असर उससे नहीं होने जा रहा है।

डा० बापू कालदाते : यह तो इन्होंने आपसे कहा। इस हद तक तो ठीक है कि उन दोनों देशों ने आपसे कहा कि इसका उन्हीं की रक्षा के अलावा कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन भारत की दृष्टि से इन संबंधों को देखते हुए आपने जैसे कहा क्लोज वाच, that Government keep all such developments under close watch and take appropriate steps as necessary to deal with them. तो मैं क्या आपसे यह पूछूं कि क्लोज वाच के माने आप क्या कर रहे हैं और नेसेसरी स्टेप्स के माने आप कौन से नेसेसरी स्टेप्स इसके बारे में उठा रहे है, इसकी भी जरा जानकारी दीजिए।

श्री सलमान खुर्शीद : मान्यवर, जहां तक क्लोज वाच का सवाल है, क्लोज वाच में हम लोग क्या क्या करते है इस वक्त पूरी तरह से बताना संभव नहीं है। मैं सिर्फ माननीय सदस्य को इतना कहना चाहूंगा कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं और जो भी हमको करना है, क्लोज वाच के लिए हम करते है। कभी भी जब हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति आती है जैसे कि अभी चीन के तीन ट्रालर जिनके बारे में हमें यह शुबहा था कि हो सकता है कोई जासूसी का काम कर रहे हो, हमने उनको फौरन हिरासत में लिया। पूरी तरह से जानकारी पाने के बाद जब हम संतुष्ट हो गए कि ऐसा कुछ नहीं है तो हमने उनको छोड़ दिया।

DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Sir, the Minister has just now said that they had held discussions with Myanmar on this issue. Now, in this year's Annual Report, on page 5, the details of whatever had taken place between India and Myanmar have been given in one full page, but nowhere has it been mentioned about this topic being discussed or about the importance of this particular matter in the relations between India and Myanmar and India and China. What is the reason for not reporting this to Parliament earlier?

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, we would have come to Parliament

if there was anything of a specific nature that was required to be reported to Parliament. Our contacts with Myanmar and China on this issue are of an informal nature. This was brought up during informal discussions of the Foreign Secretaries during the visits that had been made both to China and Myanmar. If anything of a specific nature had come to our notice, we would have certainly brought it to Parliament.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, the border areas of Myanmar are being used by insurgents, which has been creating problems in the north-east for a long time. It is still going on. I would like to know from the Minister whether, because of the new development and new alliance or new kind of arrangement between China and Myanmar for the construction of roads and other things, the Government has made any attempt to know as to what extent it will affect our national security and also whether these facilities will be used by the insurgents to import their own arms and ammunition and use them again our own country and within the country.

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, we have increasing co-operation with Myanmar on better control and better supervision on the border. In this context, we are co-operating with them on border roads.

SHRI VAYALAR RAVI: There are terrorist activities in the North-East They are using these border areas

SHRI SALMAN KHURSHEED: I will explain this. This part of our growing co-operation for control of the border, includes looking for possible infiltration by people who have insurgent tendencies against Indian state. We are satisfied that the growing co-operation will be of help to us in this manner.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Chairman, the hon. Minister mentioned that they were having informal talks with the military regime in Myanmar. We know that there is no democratic, elected government there. India is a democracy. This will continue as long as there is a military regime there. Its intentions cannot be helpful to our country. Therefore, may I know from the hon. Minister whether India has taken up in the United Nations the issue that an elected government is to be installed there and whether Myanmar has made any attempt to be a member of the SAARC?

SHRI SALMAN KHURSHEED: Sir, as far as I am aware, there is no move to include Myanmar in the SAARC. Certainly, there is a move, and some thought is being given to include Myanmar in the ASEAN. As far as its internal government is concerned, it is not for India to comment on its internal government and on the internal affairs of the State. Of course, India continues to support democratic movements the world over and to give whatever moral support democracy needs in the United Nations

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : सभापति महोदय, म आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि जिस प्रकार की सहायता और सहयोग चाईना और म्यांमार के बीच हो रहा है क्या उस प्रकार के आश्वासन हमारी तरफ से दिए गए हैं, उनकी सड़कें बनाने के, उनके पोर्ट बनाने के, उनके आयल एक्सप्लोरेशन इत्यादि इन सब मामलों में हम भी उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है और उसकी उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई ? "ब" भाग मेरे प्रश्न का यह है कि क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि औपचारिक और अनौपचारि, फार्मल और इनफार्मल यह जो कांटेक्स्ट है इनमें क्या भेद वह एक्स्टर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की दृष्टि से करते है, एजेंडा भेजा जाता है या बिना एजेंडा भेजे और उसी को लिखा जाता है जिसका कि एजेंडा भेजते है, बिना एजेंडा के आपस में बात करने या मिलने का कोई जिक्र भी नहीं करते ?

श्री सलमान खुर्शीद : सर, पहले सवाल का जवाब यह है कि चीन को म्यांमार के उन

क्षेत्रों की जरूरत ज्यादा है जहां पर चीन अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है और हम मानते है कि शायद इसीलिए वह वहां पर सड़कें भी बनवाने का प्रयास कर रहा है। जहां तक भारत के संबंध का सवाल है म्यांमार से तो हम हर किस्म के व्यापार और दूसरे जो हमारे संबंध बढ़ सकते हैं उनको बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इन चीजों में दोनों तरफ से अगुवाई करनी पड़ती है । उनकी तरफ से जो भी अगुवाई होगी उसका हम जरूर सही तरह से जवाब देंगे और प्रयास करेंगे कि हम पूरे संबंध उनसे और मजबूत बनाएं । जहां बात रही औपचारिकता की बात-चीत की, चर्चा की, उसमें जो चीज एजेंडा पर आती है उसका रेकार्ड जरूर बन जाया करता है । बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसको माननीय सदस्य जानते हैं, जो इनफार्मल तरीके से की जाती हैं, जिसका कभी असर होता है। अगर उनमें से कोई बात बढ़कर निकलती है तो उसका रिकार्ड भी कर लिया जाता है ।

MR. CHAIRMAN: Question No. 406

SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of Railways be pleased to state. ...*(Interruptions)*...

I want to read it. The public should know what it is. We just give the number, and it does not make any sense to the public.

MR. CHAIRMAN: You speak after the Minister's reply.

World Bank report on privatisation of Railways

*406. SHRI K. R. MALKANI:†

DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government has seen the World Bank report on Indian Railways, briefly reported in the Indian Express of 15th April, 1995.

(b) if so, what is Government's reaction thereto and whether the proposed privatisation of Indian Railways would lead to a steep all-round rise in freight and fares;

(c) whether Government had asked for World Bank advice and made Railway records available to them and if so, what are the reasons therefor; and

(d) whether Government would consider keeping World Bank and other such Western instruments of World control at arms length to maintain autonomy and independence in the functioning of Indian Railways?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(b) to (d) The World Bank report does not propose privatisation of Indian Railways. The Bank has, however, suggested corporatisation of Indian Railways and also of its production units to begin with and to privatise the Production Units in the long run. Government had not asked for any advice from the World Bank. The published documents and material available on Indian Railways have been used and no additional records have been made available to them. These are only suggestions and Government has no such proposal under consideration at this stage.

SHRI K. R. MALKANI: (a) Is the Government not trying to make a distinction without difference? The World Bank has said, "privatisation". There is a newspaper report saying that the World Bank is for privatisation. You say that they want corporation. Would you like to clarify the difference between privatisation and corporation? If it is intended to be a government corporation, then the Railways are already that. Why exactly are you making this distinction without a difference?

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri K. R. Malkani.